Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 07-03-2006
Participants : Pal Shri Rupchand,Dangawas Shri Bhanwar Singh,Adsul Shri Anandrao Vithoba,Preneet Kaur Smt. ,Kumar Shri Shailendra,Singh Shri Ganesh Prasad,Mahtab Shri Bhartruhari,Singh Shri Lakshman,Rao Shri K. Chandra Shekhar,Mahajan Smt. Sumitra,Maheshwari Smt. Kiran,Verma Shri Rajesh,Dikshit Shri Sandeep

an>

Title : Combined discussion on the Budget (General) for 2006-2007, Supplementary Demand for Grants in respect of Budget (General) for 2005-2006 and Demands for Excess Grants for 2003-2004.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up item nos. 15 to 17 together for discussion. The time recommended by the BAC for all these items is 12 hours. I request hon. Members to give only suggestions during the debate. Otherwise, we will have to sit late in the night also.

Motions moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 10, 12 to 15, 17 to 22, 24 to 26, 29 to 31, 34, 36, 40, 41, 43, 46 to 51, 53, 54, 56 to 62, 65, 71 to 73, 76, 78, 79, 81 to 88, 90 to 101, 103 and 105."

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended the 31st day of March, 2004, in respect of the

heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 15, 16, 24, 27 and 67."

Shrimati Sumitra Mahajan will speak now.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जनरल बजट पर चर्चा करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैंने पूरा बजट देखा है। हालांकि हमारे वित्त मंत्री जी आंकड़ों का खेल बताने में काफी होशियार हैं लेकिन मैं एक सामान्य महिला एवं सामान्य गृहिणी हूं। जब वित्त मंत्री जी ने बजट की शुरुआत की थी तो बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ रेट के बारे में कहा था। आज पूरे हिन्दुस्तान में ग्रोथ रेट पर ज़ोर-शोर से चर्चा की जा रही है। अगर उस आधार पर हम इस बजट को देखें तो ऐसे लगने लगा कि The Budget is filled with missed opportunities. 'मौका चूका बजट है', एक अच्छा मौका मिला था जिसे एन.डी.ए. सरकार ने इनके लिये छोड़ा था। एक अच्छी परम्परा कायम की और ग्रोथ रेट भी अच्छा छोड़ा था। उसके बाद मौसम भी ठीक था लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद कोई अच्छी policy direction for long-term sustainable growth. यह दे सकते थे। मुझे कभी-कभी लगने लगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर मोगरे के फूल होते हैं लेकिन अगर मोगरे के फूलों से फ्रेगरेंस निकालकर सेंट बना दिया जाये और आखिरी कोने तक पहुंचा दिया जाए फिर तो कुछ बात बनती। एक छोटा गजरा बनाकर छोड़ दिया या बड़ा गजरा बनीकर, इधर-उधर फैंक दिया या फूल इधर-उधर फैंक दिये गये, वे सूख गये ऐसी ही स्थिति कुछ इस बजट की है इसके साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसा ही किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने भााण में अपनी संकीर्ण मानसिकता या संकीर्ण प्रवृत्ति का परिचय दिया है। मैं मानती हूं कि चुनाव का मौसम आने वाला है और उधर वाले लोगों की रग-रग में अपीज़मेंट ऑफ माइनौरटीज पौलिसी कूट-कूट कर भरी हुई है। इसलिये हमें उस पर भी आश्चर्य नहीं होता। आप माइनौरटीज़ के लिये देते जाओ, बांटते जाओ, उर्दू भााा के लिये तीन करोड़ रुपया दे दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसी के साथ-साथ अगर Central Institute of Promotion of Indian Languages या सिंधी की तरफ ध्यान देते तो अच्छा रहता लेकिन वैसा नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। वैसे तो यह पूरा बजट - The Budget is full of rhetoric and populism. क्योंकि चुनाव आने वाला है, इधर-उधर की बातें करनी हैं लेकिन इस संबंध में ठोस काम की बात होती, अगर हम हिन्दुस्तान के लोग उस बात को करें तो इनको समझ में नहीं आती cè[RB25]।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी बाहर का आदमी बोलता है, तो हमारी समझ में जल्दी आता है, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। इसलिए जो बात इंटरनैशनल हेराल्ड इंस्टीट्यूट और हमारे यू.एन. डै

वलपमेंट प्रोग्राम्स की ह्यूमन डैवलपमेंट रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने लिखी है, उसे बहुत ध्यान में रखने लायक है। मैं उनका एक वाक्य बताना चाहती हूं। उन्होंने लिखा है - "A hundred Bangalores will not solve India's tenacious poverty problem." आपने इस बजट में बड़ी टैक्नौलौजी की बात की है, उससे बढ़ने वाले एम्पलॉयमेंट की बात की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में हिन्दुस्तान में एक ऐसी समस्या है जिसे दूर करना नितान्त आवश्यक है और वह है माल नरिशमेंट। Every third child is malnourished. अगर हम कहें कि हिन्दुस्तान की आने वाली आबादी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे माल नरिशमेंट के शिकार होंगे, यह बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि इसमें देश की भावी पीढ़ी को संभालने वाले बच्चों की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए पूरे बजट पर बात करना मुश्किल है। चूंकि मैं खुद बाल विकास विभाग की मंत्री रही हूं, इसलिए एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं, जो मेरे ध्यान में आई है। मंत्री जी ने बजट में आई.सी.डी.एस. का यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात बहुत जोर-शोर से कही है। आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम में न्यूट्रीशन भी दिया जाता है और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी चिन्ता की जाती है। इस प्रोग्राम को आपने बढ़ाने की बात कही है और बड़े जोर-शोर से कहा कि हमने पैसा बढ़ा दिया। मैं बताना चाहती हूं कि आपने कितना धन दिया और कितना बढ़ाया। पहले इस मद में 3315 करोड़ रुपए थे, अब आपने इसमें 4087 करोड़ रखे हैं। इस प्र ाकार देखा जाए तो केवल 772 करोड़ रुपए ही बढ़ाए गए हैं। यहां मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से ही आप चलाते हैं। मैं समझती हूं कि 2006 में यह असिस्टेंस बन्द हो जाएगी और हमारे सिर पर ही पूरे प्रोजैक्ट का भार आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे। चूंकि यह बाल विकास और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना है, इसलिए इसे आप बन्द तो नहीं करेंगे, इसे आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन इसे चलाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। हालांकि आपने इसमें कहा है कि हम आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और इस प्रोजैक्ट का और विस्तार कर रहे हैं - यह अच्छी बात है, यह भी अच्छा हुआ कि बाल विकास के कार्यों से संबंधित मंत्री महोदया आ गईं। बजट तो आपने बढ़ाया, लेकिन बहुत कम बढ़ाया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आम आदमी की बात करती है। बजट में बड़े जोर-शोर से आम आदमी की बात कही गई, लेकिन मैं यदि बच्चों से शुरूआत करूं और पूछूं कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है, कौनसी योजनाओं की शुरूआत की है, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, जिससे बच्चों का कोई बहुत बड़ा और भारी कल्याण होता हो। आपने कहा कि बच्चों के फूड एंड न्यूट्रीशन में धन बढ़ाया गया है, मैं कह सकती हूं कि आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम में थोड़ा सा धन आपने बढ़ाया है, क्या इससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी ? इस बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगी।

महोदय, छोटी-मोटी बातों को छोड़कर, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से सामान्य व्यक्ति महंगाई से परेशान है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज स्थिति यह है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाती हूं, तो मुझसे सदैव

पूछा जाता है कि जब आपकी सरकार थी और आप पेट्रोल एवं नैचुरल गैस मंत्रालय में मंत्री थीं, तब भी गैस के दाम बढ़ते थे, लेकिन कम भी होते थे और आप इस प्रकार से कहीं न कहीं बैलेंसिग का काम करती रहती थीं और गैस भी एम्पल क्वांटिटी में मिलती थी, लेकिन इस सरकार के समय में तो दाम बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते और सारे गैस सिलेंडर हवा हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। कीमतें बढ़ती हैं और गैस की आपूर्ति भी नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस देश के लोगों को महंगाई झेलने की आदत हो गई है और वे यह मानकर चलते हैं कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तब-तब महंगाई बढ़ेगी ही। वित्त मंत्री जी बार-बार आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी इस देश के गांवों में रहता है। हमारे देश का किसान आम आदमी में ही आता है। जब हमारे कांग्रेसी मित्र कोई नारा देते हैं, तो हम डर जाते हैं क्योंकि पहले इन लोगों ने नारा दिया कि 'गरीबी हटाओ' लेकिनइन्हीं के समय में महंगाई बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि गरीबों के हटने की बात हो गई[rpm26]।

यह आम आदमी का...(व्यवधान) एन.डी.ए. ने क्या किया, वह भी जाते-जाते मैं बताऊंगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please. जब आपकी पार्टी का टाइम आयेगा, तब बताइये।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अब ये आम आदमी का नारा दे रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb. अभीआपकी पार्टी का बहुत टाइम है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आम आदमी का नारा देकर, जो आम किसान है, उस आम किसान को एक प्रकार से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज उस किसान की जब बात की जाती है तो उस किसान के लिए हम क्या दे रहे हैं? हो सकता है कि आप गांव में जाते होंगे, मगर कितनी सिंसियरली आप इन सब चीजों की चर्चा करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बातें तो आपने बड़ी-बड़ी की हैं और उसमें आपने हमारे सन्त तिरुवेल्लूर की भी बात की है। The world is his who does his job with compassion. यह कम्पैशन शब्द है, कौन सी दयालुता आपने की है, क्या आपने दिखाया है, आपने कहा तो है, I am prepared to go the extra mile to come to the aid of our farmers. एक्सट्रा माइल तो क्या, एक्स्ट्रा इंच भी आप नहीं गये हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि एक लाख रुपये के कर्जे पर केवल दो परसेंट तक ब्याज की छूट आपने दे दी, क्या उसे आप भरोगे - ब्याज के परसेंटेज में कम करने से बात नहीं बनेगी। बैंकों के भरोसे आपने उनको छोड़ दिया। क्या कभी गांव में जाकर देखा है कि किसानों की हालत क्या है, आज किसान की आवश्यकता किस बात की है। केवल ऋण ही ऋण देते जाओ, इस तरह से विकास नहीं होता है। कहीं आप उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत - इससे काम नहीं चलेगा। किसान वह भी नहीं कर सकता है, ऋण मिलने के बाद भी वह घी नहीं पी सकता, उसको मरना ही पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। उस किसान के लिए आज जो आवश्यकता है, उन्नत खेती की, आज किसान की आवश्यकता है, नई टेक्नोलोजी देने की, आज किसान की आवश्यकता है कि जहां हम ग्लोबलाइजेशन की बात

कहते हैं, विश्व करीब आ रहा है, आपने इसमें कई बातें की हैं, इस बजट में ड्यूटीज़ कम की हैं, इसके परिणामस्वरूप यहां बाजार भरते जाएंगे, लेकिन हमारे किसान की उपज एक्सपोर्ट हो जाये, उसके लिए भी कुछ टेक्नोलोजी सिखानी चाहिए। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे किसान क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ाकर भी वह समझ जाये, आजू-बाजू की स्थिति की मैं एक छोटी सी बात बताती हूं। आज हमारे यहां जो बाजार है, वह पूरे आस्ट्रेलियन एप्पल से भर रहा है। सामान्य आदमी जो सस्ता और अच्छा दिखे, वह तो खरीदेगा ही, उसके साथ ही हमारे यहां का जो एप्पल ग्रोअर किसान है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ? वह तो मर रहा है। क्या हम उसे कुछ टेक्नोलोजी सिखा रहे हैं कि कैसे क्वालिटी में सुधार करके आप उसे बाहर बेचें। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे रैड चिली है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे यहां की लाल मिर्चे एक्सपोर्ट हुई थी। हमारी रैड चिली में पेस्टीसाइड्स की मात्रा ज्यादा है, यह कहकर उन देशों ने उस रैड चिली को वापस तो नहीं किया, लेकिन वहां उसे एक प्रकार से पानी में डुबो दिया गया। इससे हमारे देश का नुकसान हुआ है और फिर धीरे-धीरे किसान का ही होगा, क्योंकि उसकी चीज बाहर नहीं जायेगी। क्या हमने अपने किसानों को कुछ सीख देने की कोशिश की है कि कैसी हमारी उपज होनी चाहिए, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है। What is the export quality? वही बात मैं कहना चाहूंगी। हमारे गुजरात से मूंगफली जाती है। इस मूंगफली के लिए भी कहा गया कि इसमें ऐफ्सोटॉक्सीन का कंटेंट ज्यादा होता है और इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे, हम उसे नहीं लेंगे - ऐसी अलग-अलग प्रकार की टैक्टिक्स होती हैं। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगी। फ्लोरीकल्चर की बीच-बीच में बहुत चर्चा हुई थी और किसानों ने फूल उगाना भी शुरू किया था कि अब इसका एक्सपोर्ट होगा, हमारे फूल बाहर के देशों में जाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन इसमें यहां का फुल फयूमिगेट नहीं होता है, इसलिए बाहर के देशों में आज हमारे फूल भी जाने बन्द हो गये और एक्सपोर्ट कम होता चला गया। इसमें भी एक बात और है। इसमें एस.पी.एस. होता है, लेकिन किसानों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर यह एस.पी.एस. क्या है - सैनीटरी एण्ड फाइटो सैनीटरी मैजर्स के बारे में किसानों को मालूम ही नहीं है। किसानों को यह भी नहीं मालूम है कि कृाि के क्षेत्र में इण्डीजिनस नोलिज प्रोटैक्शन क्या होता है।[i27]

हमारे यहां के एक्सपोर्टर्स को भी मालूम नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। फ्लोरीकल्चर में भी ऐसा हुआ कि गुलाब उगाने वाले दो लोग, जिन्होंने गुलाब एक्सपोर्ट किया, जब वे प्रदर्शनी लगाने गए, तो फ्रांस में पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसी गुलाब का इनटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी दूसरे के पास था - फिर ये वहां क्यों ले गए। हमारे किसानों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र पर ज्यादा बल देना आज वास्तव में आ वश्यकता है। हमारे यहां नेशनल एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन है। अगर मेरी जानकारी सही है, तो वह सौ प्रतिशत वर्ल्ड बैंक की असिस्टैंस से चलता है - क्यों? हम उसे क्यों नहीं फ्लोरिश कर सकते, हम अपने तरीके से क्यों नहीं पैसा देकर उसकी टैक्नोलॉजी अपने लोगों तक पहुंचाते?

आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर का बजट बढ़ाया, लेकिन केवल बैंगलोर इंस्टीट्यूट का बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पूरा नार्दर्न इंडिया खाली पड़ी हुआ है। यहां क्या होता है, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते। हमारे यहां ऐसे कई टैक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स हैं। हमने नेशनल इन्नोवेशन फंड बनाया था, क्या

वित्त मंत्री जी यह बताने का कट करेंगे कि उसका क्या हुआ और हमने उसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किया। नेशनल टैक्नोलॉजी बोर्ड सौ करोड़ रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे किसानों को टैक्नीकल नो-हाऊ होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में अगर कुछ भेजना हो या आपको अपनी उपज में क्वालीटेटिव इम्प्रूवमैंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। यह बात किसानों तक पहुंचनी चाहिए। केवल टैक्नोलॉजी मिशन से नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी देने से अच्छा उत्पादन होता है, केवल इरीगेशन करने से नहीं होगा। जब हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि कैश क्रॉप कैसे उगाएं, वह कैसे तैयार की जा सकती है, हमारे यहां के किसान उसकी प्रक्रिया कैसे सरल बनाएं, उसके लिए ऋण कैसे दिया जाता है, माल बेचने का तरीका क्या है - यह जानकारी किसानो को होनी चाहिए। आज किसानों का माल खरीदने के लिए बड़े-बड़े एमएनसीज़ आने लगे हैं, उनकी बड़ी-बड़ी मंडियां लगने लगी हैं। वहां किसान एक दरवाजे से अंदर आता है, अपना गेहूं बेचता है, लेकिन वहीं विदेशी बाजार की फुल मार्किट लगी होती है, वह उसमें खरीदारी करते हुए खाली हाथ बाहर लौट जाता है। आज यही सब हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि केवल ऋण देने या ब्याज दर कम करने से बात नहीं बनेगी। हमारे किसानों को समझदार बनाने की दृटि से, उसे दुनिया की नॉलेज देने की दृटि से आप क्या कर रहे हैं। आपने बजट में इस दृटि से कोई प्रयास नहीं किया, जो बहुत दुख की बात है।

रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम के बारे में बड़े जोर-शोर से कहा गया। हमने रूरल इम्प्लॉयमैंट गारंटी स्कीम लागू कर दी और उसके लिए बजट में पैसा भी रखा, लेकिन इस बारे में मुझे जानकारी है कि जितना पैसा रखा गया है, क्या वह सफीशिएंट है - क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है। आपने 14,300 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ही कहा गया है कि स्कीम डिक्लेयर होने के बाद 77 लाख लोगों ने एप्लाई कर दिया कि उन्हें रोजगार चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि रोजगार की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और उतनी ही शहरी क्षेत्रों में है - 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है - इसमें आपने केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात की[R28]। लेकिन क्या ग्रामीणों को इससे रोजगार के अवसर प्रदान हो जायेंगे? जो 100 दिन रोजगार देने की बात इसमें कही गई है, वह एक छलावा मात्र है क्योंकि गांव में न्युक्लियर फैमिली नहीं होती, वहां शहरों की तरह छोटी फैमिली नहीं होती, जिसमें माता-पिता, एक लड़का और लड़की हो। गांव में सब लोग एकत्रित रहते हैं। आप जानते हैं कि गांवों में पांच-पांच भाई इकट्ठे रहते हैं। इतने छोटे से फंड से आप 20-25 लोगों के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को भी 100 दिन का रोजगार भी नहीं दे पायेंगे। अगर कोशिश भी करेंगे, तो मुश्किल से 20-25 दिन का रोजगार इससे मिल पायेगा। क्या इससे एम्प्लायमैंट की प्रौब्लम समाप्त हो जायेगी ? इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में ही इस पर चिंता जताई गई है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लायमैंट भी उतना ही बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने रोजगार देने की जो शुरुआत की है, वह केवल झुनझुना है।

इसके साथ-साथ जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने शुरू मे कहा कि आपका जीडीपी बढ़े तो कुछ पालिसीवाइज भी होना चाहिए। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में दिन-प्रतिदिन कल-कारखाने बंद हो रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम केवल सर्विस इंडस्ट्री बन

करके रह जायें, बाहर से माल ले आयें, उसे बेचें और एजेंसी बनें। आप जिस प्रकार से दूसरे राट्रों से समझौते कर रहे हैं, उससे हिन्दुस्तान शीघ्र ही एक बहुत बड़ी एजेंसी बन जायेगा। इस तरह आर्गनाइज्ड सैक्टर में करीब तीन-चार साल में 10 लाख लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। क्या हमने कभी इस मामले में सोचा है कि कैसे हम एम्प्लायमैंट की प्रौब्लम से निजात पा सकेंगे। आपने इसके लिए केवल एक छोटा सा बजट रखा है। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्री क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने अपने समय में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पूरा मंत्रालय तैयार किया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमने उस समय पांच लाख से एक करोड़ रुपये की लिमिट भी रखी थी - आपने इस बारे मे क्या सोचा है ?

अभी बीच में खादी ग्रामोद्योग आयोग का बजट आया था। मैं उस विधेयक को देख रही थी। मुझे लगा कि शायद आप खादी आयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग-अलग जोनल आफिसेज खुलेंगे, जोनल आयोग बनेंगे, जिनमें आपके कुछ लोग गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किये जायेंगे - यह बहुत अच्छी बात है - लेकिन खादी को बढ़ावा देने के लिए आपने बजट में क्या किया - कुछ नहीं किया। जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहां कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भारत निर्माण की बात कही है। यह बड़ा अच्छा शब्द है। आप भारत निर्माण की बात करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिस तरह पूरा बजट बनाया गया है, मैं तो कहूंगी कि यह बजट डायरेक्शनलैस है। इस बजट में टोटल रिसीट 5.6 लाख करोड़ रुपये की हैं, जिसमें आपने 4.88 लाख करोड़ रुपये रेवन्यू एकाउंट में रखे हैं और 0.3 लाख रुपये कैपीटल एकाउंट में रखे हैं। आप देखें कि कैपीटल एकाउंट में इतने कम पैसे रखे हैं। जो प्रोडेक्टिव नैचर की बात होती है, जिस कैपीटल एकाउंट से आगे चलकर रेवन्यू भी जनरेट हो सकता है, उसमें बहुत कम पैसे रखे गए हैं। क्या आप इससे अच्छे बजट की अपेक्षा कर सकते हैं? कौन सा भारत निर्माण करेंगे? भारत निर्माण में इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि बहुत से काम हम करने जा रहे हैं। The hon. Finance Minister is trying to take pride in the various steps. हालांकि सब स्टेप्स हम एनडीए के समय ले चुके हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि यह जो पब्लिक है, वह सब जानती है। आपने बड़ी-बड़ी बातें की हैं। इसमें एक करोड़ हैक्टेयर ...(व्यवधान) सिंचाई गांव में लाने की बात कही गई है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का समय मिलेगा तब आप अपनी बात कहिये। Please listen to her now.

...(व्यवधान)

श्रीमती कृणा तीरथ (करोल बाग) : सुमित्रा महाजन जी, जब आप यह बता रही हैं तो पिछली सरकार का भी बता दें। ...(व्यवधान[r29])

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आपकी पार्टी का समय शुरू होने वाला है। आपको भी समय दिया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, भारत निर्माण के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें एक करोड़ हेक्टेअर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में लाने की बात कही गई है, गांवों को सड़क से जोड़ने की बात कही है, जिसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There should be no running commentary.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : इसमें गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवास बनाने की बात कही गयी है, 74 हजार हैबिटेट्स को पेयजल उपलब्ध करने की बात की है, एक लाख 25 हजार गांवों में बिजली देने की बात की है, 2.3 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन लगाने की बात की गयी है। इस तरह से बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की गयी हैं, लेकिन इन सभी को पूरा करने के लिए इसमें कोई एक्शन प्लान भी होना चाहिए। यह बात मैं एक गृहणी होने के नाते कह रही हूँ। जब हम अपने घर में कोई काम करना चाहते हैं तो उसका हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई एक्शन प्लान नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। सारी बातें केवल कागजी हैं। दूसरी तरफ इन सब बातों के लिए पैसा कितना दिया गया है, मात्र 18,696 करोड़ रूपए - इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए गए हैं। वित्त मंत्री जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे भारत निर्माण कैसे होगा? भारत निर्माण तो तब हो सकेगा, जब भारत के हर युवक के पास रोजगार हो, किसानों को वास्तव में साहूकारों के ब्याज और सूद से मुक्ति मिल सके, किसानों का विकास हो और गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंचे। इसके साथ ही अगर गोल्डेन ट्राएंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसे हमने वर्ा 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आपने उसे बढ़ा कर वर्ा 2008 तक कर दिया है, उससे आपस में व्यापार बढ़ने से भारत निर्माण होगा। यही एनडीए सरकार करना चाहती थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप भारत निर्माण की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में पैसा तो है ही नहीं। इतनी छोटी धनराशि से भारत निर्माण कैसे होगा और उसमें भी आम जनता को इन सब चीजों से दूर रखते हुए आप भारत निर्माण की बात कैसे कर सकते हैं?

सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वातावरण बनना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उसके लिए हमने शुरूआत की थी। जब हम पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तब हमने बायो-फ्युल की बात की थी। हमें लगा था कि आप इसे कुछ आगे बढ़ाएंगे लेकिन आपने इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने सोचा था कि पेट्रोल में इथेनॉल का 5 प्रतिशत मिश्रण किया जाएगा, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल पर हमारा बहुत-सा पैसा खर्च होता है और इस दृटि से हमने 5 प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना कम्पलसरी किया था। अगर इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है तो हमें बाहर से जो डीजल, पेट्रोल मंगाना पड़ता है, उस पर होने वाले खर्च में न केवल कमी आती है, बल्कि हमारे गन्ना किसानों और गन्ना मिलों को इससे लाभ मिल सकता था। लेकिन आपने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। बायो-डीजल के लिए भी आपने कुछ नहीं सोचा है। अगर जैट्रोफा की खेती के बारे में हमारे लोगों को बताया जाता तो उसमें भी कई युवकों को रोजगार मिलने की संभावना थी।

मैं अगर पावर के क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल यह कहना चाहूंगी कि इस बारे में इकोनोमिक सर्वे में कहा गया है कि आज की तारीख में स्कैरसिटी ऑफ पावर के कारण लगभग तीन लाख करोड़ रूपए का घाटा हमें हो रहा है। आज पावर की हमारी आ वश्यकता 100 हजार मेगावाट है, जो आने वाले दिनों में बढ़कर 200 हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कोई परियोजना शुरू नहीं की है। कहने के लिए तो कहा गया है कि हम मध्य प्रदेश में एक परियोजना शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो काम युद्धस्तर पर करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि कौन सी परियोजना तुरन्त पूरी हो सकती है, जैसा हमने किया था[R30]।

उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इंदिरा सागर परियोजना लम्बे समय से चली आ रही थी, लेकिन अटल जी ने कहा अगर यह तुरंत पूरी हो जाती है तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा। तब उन्होंने इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे और कहा था कि दो साल में यह परियोजना पूरी होनी चाहिए। यह स्टेप हमने उस समय लिया था, लेकिन इस तरह का कोई स्टेप वर्तमान सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है।

वाटर मैनेजमेंट में कई चीजों की शुरूआत हम लोगों ने की थी। आज भी महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। पिछले बजट में रिपेयरिंग एंड रिनो वेशंस आफ वाटर बॉडीज की बात कही गई थी, लेकिन उसका क्या हुआ - इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है। अगर आलेख लेना हो तो आपको गुजरात जाकर देखना होगा कि वहां इस सम्बन्ध में नरेन्द्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में खेत तलावड़ी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत, खेतों में छोटे-छोटे तालाब बनाने में वहां की सरकार किसानों को मदद देती है। इस तरह से एक लाख के ऊपर गुजरात में खेत तलावड़ियां बनाई गई हैं, जिसके कारण सिंचाई के लिए किसानों को पानी तो मिल ही रहा है, साथ ही वाटर रिचार्जिंग में भी मदद मिलती है। नरेन्द्र मोदी जी का यहां नाम लेकर केवल आलोचना करना ठीक नहीं है, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, वे भी देखने चाहिए और इस सरकार को भी करने चाहिए। हम आपसे इसकी अपेक्षा भी करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

मैं कुछ बातें सर्विस टैक्स के बारे में कहना चाहती हूं। सर्विस की बात जब हम करते हैं, तो लगता है सेवा करना - इसमें सेवा का भाव आता है - लेकिन आपने इस पर भी टैक्स लगा दिया है। वास्तव में यह टैक्स आम आदमी पर ही पड़ेगा। आपने अपने बजट में ट्यूशन के ऊपर, कोचिंग के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया है। ट्यूशन और कोचिंग क्लास में हमारे बच्चे क्यों जाते हैं ? इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्र णाली में दोा है, कहीं न कहीं स्कूलों में पढ़ाई कम होती है। ट्यूशन और कोचिंग क्लासेज में अमीरों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे जाते हैं। इनके माता-पिता सोचते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़-लिख जाएगा तो आगे चलकर चार पैसे कमाने लायक हो जाएगा। इसीलिए वे अपने बच्चों के अच्छे भविय के लिए यह काम करते हैं, लेकिन आपने उस पर भी सर्विस टैक्स लगा दिया है। यह भी आखिर में बच्चों के माता-पिता की जेब से ही जाएगा, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग सेंटर चलाने वाले तो इसे देंगे नहीं।

इसके अलावा आपने एटीएम सर्विस पर भी टैक्स लगा दिया है। जिस दिन आपने अपने बजट में इसका उल्लेख किया, उसी दिन से लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। मेरे ही क्षेत्र से तीन-चार पेंशनर्स का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि हम वृद्ध लोग बैंक में जाकर लाइन में खड़े नहीं हो सकते इसलिए पास ही के एटीएम सेंटर से अपनी पेंशन निकालते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने उस पर भी सर्विस टैक्स लगा दिया है। एटीएम सर्विस पर क्यों टैक्स लगाया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई भी बैंक बैंकिंग व्यवसाय करता है, तो वह अपने पैसे से नहीं करता, हम लोगों द्वारा जमा किए हुए पैसे को ब्याज पर देकर व्यवस्थापन का खर्च निकालता है। आपने उस पर कर लगा दिया है, तो वह भी आम लोगों की जेब से ही जाएगा।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सर्विस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इतना जरूर मेरी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पर यह सेवा कर काफी प्रभाव डालेगा और उसे जरूर प्रभावित करेगा।

मैं आखिर में एक बात और कहना चाहती हूं। जैंडर बजटिंग की बात यहां बड़े जोरशोर से की जाती है। एनडीए की सरकार ने ही इसे शुरू किया था। उस समय मैं महिला विकास मंत्री थी और मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमारे बजट में इस आधार पर कुछ बात होनी चाहिए। इसलिए यह कॉन्सेप्ट उस समय शुरू हो गया था। मुझे उम्मीद थी कि आप जैंडर बजटिंग की बात करेंगे और उस सम्बन्ध में कोई ठोस बात करेंगे या महिलाओं के लिए नीति बनाएंगे - केवल विभागों के लिए पैसा रख देने से ही बात नहीं बनती। कोई ऐसी पालिसी बननी चाहिए, जैसे आईसीडीएस है, जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था। जैंडर बजटिंग करना, महिलाओं को एनेबल करना है। उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए हमने स्त्री शक्ति पुरस्कार की बात की थी और पांच ऐसी महिलाओं को पुरस्कार के लिए चुना जाता था जो अपने जीवन में कुछ कर गुजर के दिखाएं[R31]।

आज तक इस सरकार ने चार सालों तक न तो कोई पुरस्कार नहीं बांट और न उसे आगे बढ़ाने की बात ही की। मैं यहां एक दूसरी बात कहना चाहती हैं। जेंडर बजटिंग में हमारी कल्पना थी कि महिलाओं तक लेटैस्ट टेक्नॉलाजी पहुंचे। आप देखिए कि अगर 80 प्रतिशत खेतिहत मजदूर पूरे देश में हैं, तो उनमें से 60 प्र

ातिशत महिलाएं हैं। महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं, तो कई बार उनको छः-छः महीनों तक घर छोड़कर जाना पड़ता है। ये मजदूरी करने वाली जो महिलाएं हैं, ये अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं। उनके लिए वूमेन फ्रैंडली टेक्नालॉजी या वूमेन फ्रैंडली टूल्स की भी एक बात आती है। अगर वे खुर्पी भी चलाएं, अगर इसकी आवश्यकता के अनुसार वे खुर्पी भी बनाती हैं, तो वह ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके लिए हमने चेन्नई में वूमेन टेक्नालॉजी पार्क की शुरूआत की। मैं जानना चाहती हूं कि उसका क्या हुआ? उस पर अभी तक कितना काम हुआ? वूमेन फ्रैंडली टूल्स बनाने की ओर आपने कितना ध्यान दिया? जेंडर बजटिंग में यह बात भी आती है।

राट्रीय महिला कोा की बात भी इस संदर्भ में आती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने उस समय यह सोचा था कि धीरे-धीरे हम राट्रीय महिला कोा के कारपस को सौ करोड़ रुपए तक पहुंचायेंगे। हमने उसकी शुरूआत भी की थी। मैं उस समय मंत्री थी और इसलिए हम उसे आगे भी लाए थे लेकिन आज वह वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। केवल भााणों में बात हो रही है कि उसे आगे पहुंचाना है लेकिन आज तक उसे इतने सालों के बाद भी आगे नहीं पहुंचाया गया है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि जब हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं, तो केवल थोड़ा इधर और थोड़ा उधर पैसा रखने से काम नहीं चलेगा। वूमेन को इनेबल कैसे किया जाए, वह सशक्त कैसे हो, वह जहां काम कर रही है, टेक्नालॉजी का ज्ञान उस तक कैसे पहुंचे, इस दृटि से भी इसे देखना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री जी कुछ-कुछ बोलते हैं, तो महिला होने के नाते मुझे समझने में देर लगती है, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि "Quality of Government expenditure has increased." मैंने जब यह वाक्य पढ़ा, तो मैं ढूंढने लगी कि क्वालिटी आफ गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर किसे कहेंगे? I am sorry that I beg to differ, क्योंकि क्वालिटी आफ एक्सपेंडीचर को अगर देखना हो, तो उसे एनडीए के शासन काल में देखें। उस समय जो काम हमने किये थे, जेंडर बजटिंग की शुरूआत की, न्यूक्लियर टेस्ट की बात की, पावर जेनरेशन के लिए हमने इनीशिएटिव लिया था, हमने उस समय क्राप्स लोन पर ब्याज, जो 14 से 18 प्रतिशत तक था, उसे 9 प्रतिशत तक ले आए थे, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री तैयार की थीं और लघु उद्योग के लिए छूट दी थी, रोड्स के काम शुरू किए थे - मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसे क्वालिटी आफ एक्सपेंडीचर कहते हैं।

मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती है, मैंने उसे कहीं पढ़ा है, उसका खुलासा मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगी। देश की कुल आमदनी का 81 प्रतिशत भाग हमारा कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता हैं, वहीं यह भी कहा गया था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, उससे हमारे कर्ज को चुकाना भी संभव है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हमने विदेशी मुद्रा को अमेरीकी प्रतिभूतियों में लगा रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उनसे वास्तव में पर्याप्त मात्रा में ब्याज आता है? हमने ऐसा क्यों किया है? आप पास्ता खाने की बात करते हैं और कहते हैं कि पास्ता खाइए, आप कहते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, तो कोका-कोला पीजिए और इसीलिए आपने उस पर टैक्स कम कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा आपने क्यों किया? प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि "I believe that the needs of the people of India must become the central agenda for our international co-operation." Why

international, नेशनल की भी तो आप बात करिए। क्या यह इंटरनेशनल को-आपरेशन है, जो आपने ऐसी प्रतिभूतियों में पैसा लगाकर रखा है? मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी बजट बनाते समय, केवल आंकड़ों का खेल नहीं चलता, आंकड़ों को तो ध्यान में रखना ही है, मगर देश की परिस्थिति, देश के वातावरण को भी ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए। यह बजट देश का नहीं है, इसमें बुश को ध्यान में रखा गया है, ऐसा कहीं न कहीं इस बजट को देखकर लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, if you permit me, then I will speak from here itself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can speak from there.

SHRI K.S. RAO: Thank you. Sir, I rise to support the Budget presented by our hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram. The reason being that without increasing the taxes and by just widening the tax-base he could present an excellent Budget.

I heard with rapt attention the speech given by the hon. Member Shrimati Sumitra Mahajan. I definitely understand that by virtue of her belonging to the BJP, an Opposition Party, her duty is to criticise the Ruling Party and the Government Budget. Therefore, she can never support it. If I were to be in that seat, then I might also have done the same thing. The only point that I wish to make here is that she possibly chose the areas to criticise without any strength, and without any base. I will give you the statistics to support this view.

Sir, kindly allow me to begin with what she was telling about the Congress Government adopting only the populist policy like *garibi hatao*. I agree that the Congress Party adopted the policy of populism. The Congress Party made a slogan, and then tried to implement the slogan of *garibi hatao*. On the other hand, I would like to ask this from them. Is there one instance where the BJP has ever said anything about the poor people, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities or even the disadvantaged persons in the society? The only slogan, which was very very popular with them time and again and day in and day out was the *rath yatra*, construction of temple at Ayodhya, etc.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): They also talked about India shining.

SHRI K.S. RAO : These are the issues on which they made slogans, and here is a Party, which speaks about the poor. I would have understood if she were to make criticism on the issue of doing something more for the poor than what is being done today. I would also have appreciated it, but it is not the case.

Please allow me to once again give a comparison between how the Congress Party thinks, and how the BJP thinks. The Congress Party and the UPA Government thinks in terms of secularism. On the other hand, they think on the basis of Hindu gods even on a issue like securing votes. We try to secular votes by serving the poor people of the society, and they try to get votes on the basis of provoking Hinduism. What amount of difference is there between the two Parties? The basic difference is in the method of thinking and concepts itself.

Similarly, they think about corporate sector only, and never about the farmers. Today, she did touch upon the issue of farmers, and the agriculture sector. She did speak about the farmers, but it was not in depth. She only referred about the matter of farmers. Did they ever speak anything about the farmers, poor people living below the poverty line, etc. during their tenure in the Government? Every time, they used to speak only about disinvestment, exports, corporate sectors, shares, etc. Was there anything beyond these issues?

Today, we are speaking about reviving the public sector undertakings. What was their thinking on this issue? They were thinking of closing the public sector undertakings, disinvestment, selling, etc. This is how they were thinking with regard to this issue.

I would like to share some more statistics with the august House. If they were to think of packages, then they would think of giving packages only to the rich, and never about giving packages to the farmers[ak32].

It is the Congress Government which is thinking in terms of giving a package to the farmers and settling the things. They have already given directions to the banks that in regard to the arrears of farmers, a similar package must be applied in the case of farmers. Have they ever thought of the rural areas? They only think about the urban areas, be it Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai or something of that kind. In their history, they never thought of the rural areas. It is here that this Government has thought of the rural areas, and the people who are below the poverty line. Have they ever thought of the poor people who are below the poverty line? Did they bring one scheme in their lifetime?

Today, this Government has thought of giving pension of Rs. 200 per month for all those unfortunate people. If the people in privilege positions drawing about Rs. 50,000 per month can deserve pension throughout their lifetime, what happens to the poor people living in the villages who start working from the age of 10 and up to 60 years? If you go to the villages, you can see umpteen number of poor people who are below the poverty line living in huts. Even their children are not in a position to look after them. They are living like orphans. This Government has thought of them and they came out with a policy or declaration that they will pay Rs. 200 per month directly to all these poor people through the banks and post offices. Do you think of them any time? Did she even mention this? The answer is, 'no'.

They think of the organised sector, but they never thought of the unorganised sector. There are 28 million people in the organised sector, whereas there are 400 million people in the unorganised sector and that too living in the villages. They are the people who are to be taken care of first. Did they discuss about them? We discussed about them.

In regard to health, education, housing, drinking water, electrification, giving house connections to the poor, we made schemes, and they have not made any schemes. I am not making any shallow speech. I will give you the details of how much

allocation has been made to every item. I will now take up one by one the points raised by my hon. colleague, Shrimati Sumitra Mahajan. She said that the Finance Minister had frittered away the resources, that he was narrow-minded and that he came forward with populist proposals only because elections are due in some States. Whose elections is she talking about? It is not his elections or my elections. There is no need for him to do anything here.

She talked about the common man and she talked about suicides by farmers. When did it happen? That has happened when their Government was in power. She talked about technology and agriculture. I do agree with her on that point. The point here is that research and development was neglected in this country for quite a long time. But what have they done during their tenure? I am now giving you the statistics. Do you know what was the amount that they have allocated in their Budget towards Science and Technology? It was Rs. 30 crore. This present Government has allocated Rs. 13,000 crore. Where is the comparison? There is no comparison at all. We have realised that this country is not growing as much as it should grow because of lack of research and development. So, this Government has allocated that much money..

Now, I will go point by point. She was talking about employment. Have they ever thought of that? On the contrary, my hon. colleague was making fun of NREGP (National Rural Employment Guarantee Programme). We passed that Act. In the rural areas, poor people were not getting work throughout the year. They are certainly getting work for some days. We wanted to cover this gap and we thought that we will provide 100 days of work to one member in each family. She said, and I do not know how she imagined that to be true, out of 25 people who are living under one roof, the Government is providing employment to only one person. That is not our idea. Our idea is to provide employment to one person in a family comprising two adults and three or four children. I never had the opportunity of coming in contact with a family comprising 25 members living. As per her calculations, there may be 23 children with two adults living under one roof, which I am not debating. The National Rural Employment Guarantee Programme was made by us and not by them.

She said that this Government has forgotten the small-scale industries. Not only small-scale industries, but even medium enterprises were brought under the small-scale industries today by this Government, limits have been increased, and substantial

allocations have been made. Credit Guarantee Fund was made available to take care of the risk, as far as these small-scale industries are concerned. Even here, it is the Congress Government which has done this, and they have not done anything.

In regard to Bharat Nirman, she made fun of it by saying how can we bring one crore of hectares under cultivation with the kind of allocation that was made. For her information, under this programme, the Congress Government in Andhra Pradesh brought 65 lakh hectares of land under cultivation till date[R33].

Not only making announcements, funds are allocated for every scheme. I will explain the quantum of funds allocated scheme by scheme.

Shrimati Sumitra Mahajan referred to the Golden Quadrilateral project. The only thing that is left for them to talk of their Government is that it is their Government which started the Golden Quadrilateral project. I do not think that a day passes in the Lok Sabha without their talking about Golden Quadrilateral! They keep repeating Golden Quadrilateral, Golden Quadrilateral and Golden Quadrilateral. What actually was the quantum of work done during their tenure under the Golden Quadrilateral project? It was 1.8 kilometres road per day. Today, work of 4.48 kilometres is being completed everyday under this project. This Golden Quadrilateral project is going to be completed by June this year, not next year. We have not left it at that. We have also started work on the project of corridors. We know how important it is. So, it is not that only their Government started it.

Coming to power, yes, this Government has said that it would give electricity connections to all those people living below the poverty line. The number of such households runs into crores. The programme is already being implemented in every State. Out of Rs.1500 expenditure incurred on each connection given to below the poverty line households, we said that only Rs.125 would be paid by them and the rest of it would be borne by the Government. Have they ever thought of that? Is it not being implemented today in the villages?

She talked about the water bodies and praised Mr. Modi, of all the people, on this occasion. He is an example of the former Chief Minister of Andhra Pradesh ... * ... He also thought in the same way and spent Rs.1600 crore on *Neeru-Meeru* programme. Not even one crore rupees worth of work was done in the entire Andhra Pradesh. All the Rs.1600 crore was swallowed by the people of his party. It seems he brought out that scheme to feed his party members so that it can be spent during the next elections. Maybe the same thing has been done in the other case. I do not think any real work was done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not mention names of those who cannot be present here. नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

SHRI S.K. SHARVENTHAN (PALANI): She mentioned the name of Mr. Modi, Sir.

SHRI K.S. RAO : She mentioned his name. That is why I mentioned the names.

I will now come to the things this Government has done one after the other. She talked as if her Government had rolled out a red carpet for this Government when it came to power two years back. She said that they had done everything and this Government has just followed. If that were to be so, why had their GDP remained where it did in their tenure of four-five years? If it had been for one year, one can understand. One can blame the previous Government if it were to be

---

* Not Recorded

belonging to another party. It is they who ruled the country prior to that also. They ruled the country for the last four-five years. Growth during their tenure has not exceeded five per cent, except in the last three years.

In the very first year of the Congress Government, growth has gone much beyond what they achieved. If it were to be only because of them, how come the growth rate during the second year also has been 7.5 per cent? It was 8.1 per cent in the third year. We would like to reach ten per cent. So, where is the comparison? How can they say that it is inherited from them because of their good work? If it were to be good

work, it would have shown throughout their tenure of five years and not just in three years.

Shrimati Sumitra Mahajan talked about inflation. What is inflation today? It is four per cent, the lowest in the history of India. Industrial growth is equally good. Agriculture has recorded a growth rate of 2.3 per cent at 209 million tonnes. It was less than one per cent sometimes in their tenure. She said it is all a jugglery of figures. I am not doing any jugglery. I am just quoting the figures. She herself mentioned that she is not very familiar with the figures. … (*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): The 2.3 per cent growth that you are talking about is achieved through the plantation crops. It does not come under the Ministry of Agriculture. Agricultural input extension is lacking under your Government.

SHRI K.S. RAO : Not only industrial growth. There has been a capital formation of 30.1 per cent. It happened never in the history. Domestic savings have been registered at 29 per cent. This has been the highest figure in the entire history of India[KMR34].

15.00 hrs.

They never thought of agricultural credit. This Government promised that it will double the credit in three years. It has not just promised that but it is exceeding its own promise in terms of providing credit. Not once in the history one would see a Government keeping up its commitment. Here is an evidence. What did they do? There is also a mention of reduction of interest to seven per cent, a reduction by two per cent. Did they ever think of it? They thought of reducing the interest for car manufacturer but not for the farmers. They mentioned zero per cent during their tenure. For farmers, our Government has reduced the interest rate.

In regard to the gender budgeting, she just mentioned that they made a beginning. I would like to explain as to how they made a beginning. We have

allocated a sum of Rs.28,737 crore for gender budgeting. Is it not a huge figure? Let them dispute the figure if it is wrong.

Now, I come to Bharat Nirman programme, which she referred to. The allocation made for this year under this programme is Rs.18,696 crore; last year, it was Rs.12,160 crores. That means, there is an increase of 50 per cent in one year. It is not just five per or 10 per cent. The allocation for irrigation under the AIBP was enhanced from Rs.4,500 crores to Rs.7,120 crores. Six lakh hectares of land would be brought under irrigation.

Under the Accelerated Rural Water Supply, out of 56,270 villages to be provided water connection, already 47,546 villages are connected by January this year. Another three months time is left. That means, we would be going beyond the set target.

In the last year, for construction of rural roads, a sum of Rs.3,749 crores was allocated. This year, he made a provision of Rs.5,337 crores. By September, the set target would be reached.

How did they interpret housing in their Budget - 1999-2000? The promise given by them was wonderful and beyond imagination. They stated that for housing, they had done a wonderful thing. What is that wonderful thing they had done? For housing in the urban areas, they replaced the ULC Act. By doing that, they thought that their job was over. By doing that they think that they had done an immense service to the poor for their housing. Is that a solution? For rural housing, what did they do? For strengthening the housing finance, their Government had asked the national banks to lend to NBFCs, private financial companies to lend for housing. What kind of imagination! They wanted to strengthen the private financiers to finance for housing. This is how they think. She mentioned that not only agriculturists, farmers, but also several hundreds of weavers committed suicide because for them living has become such a bad thing. Then, in what manner, they thought of coming to their rescue? They said that they would provide services, technical and marketing only. By saying that they think that their job was over, not by allocating funds. What

has this Government done? This Government has not only allocated funds but it has also provided insurance scheme for healthcare, accidents, death. The Government has assured that it would start `Yarn Banks' so that they would be provided with the supply of uninterrupted yarn and without any delay; and as and when they require funds, they would get the same. There must be a practical solution. They never thought of that.

In the field of healthcare, what did they do? For providing healthcare for the poor, they said, integrate and synergise existing programmes and that the Central Government would give funds to the *Gram Panchayat,* who come up with their own contribution. That is all they said; and there is no allocation of funds. If the village worker comes up with his own contribution, then, he will be given funds. How many village workers come to them?

They wanted to start the schemes in the fields of health care and education. It is much more surprising. The biggest weapon for the poor to come up in life is only education[s35]. Even by shutting generation of power for 24 hours, they could not secure one house site, one shelter to live or even one acre of land. What was the promise they gave? About education, they said that they would provide a school within a radius of one kilometre. It is a very good idea. I appreciate that. They said that wherever schools are not there, they would provide one school within a radius one kilometre. We do not deny that. What have they done to achieve that? They said that premises or building, cash and teachers would be provided by the panchayats. Then what is it that they would do? If the gram panchayat has to arrange for a building, then what will they do? They will announce a policy that they would provide a school within a radius of one kilometre. This is how they would do. I am reading only those things which are written here.

She was talking about employment. She talked about the Swaran Jayanti Gram Swaraj Yojana. She said that the gram panchayat would implement the scheme and the Central Government would bear 20 per cent of the cost. Which gram panchayat has got the capacity to bear 80 per cent of expenditure? They are not even able to pay their own salaries. For everything, they are depending on the Central Government fund or the funds from the State Government. If 80 per cent is to be borne by them, will there

be an opportunity for any poor man to get educated in a village? How can they think of education, health and housing?

I will come to what this Government has provided for health or for housing. This Government has provided Rs.24,115 crore for education, which is 31.5 per cent more than what was provided last year. Now this year particularly under the Sarva Shiksha Abhiyan, they have provided Rs.10,041 crore. They have a clear target of recruiting 1,50,000 teachers. Five lakh classrooms will be constructed in addition to what is already existing. Statistics reveal that there are 5.7 lakh villages in the country. We are now providing five lakh rooms in this Budget.

The Mid-Day Meal Scheme is there. We are providing funds for it. We are creating an ambience there. We are providing an atmosphere in the school so that the child thinks in terms of coming to the school and enjoy more than sitting in the house. Not only that. This Government has got a scheme for a girl student. If a girl student passes class VIII and enters into the Class IX, the Government will deposit Rs.3,000 in a bank which she can draw, the moment she reaches 18 years of age. They were talking about women's empowerment. What more is required? We have started it right from the childhood. We are providing incentives for them to educate the girl child. They had never thought of that. 'Women's Empowerment' was only a slogan. Will it bring real women's empowerment?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : फिर वुमैन एमपावरमेंट ले आईये।

SHRI K.S. RAO : I did not utter a single word when she was speaking.

About rural sanitation, under the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, there is an allocation of Rs.4,680 crore in this Budget with a specific target that 56,270 habitations would be connected with water; 140,000 schools would be given drinking water facilities. It is not merely an allocation of money, he has mentioned about it in the Performance Budget about the kind of action that is going to be taken in comparison to the provisions made, targets set and achievement made. Have they ever done that? Did they ever cope up with the commitment?

Under the ICDS, this Government has provided Rs.4,087 crore and wants to start, in addition to the existing ones, 1,88,168 centres. Apart from that, Rs.4,067 crore is allocated[p36].

Even now, the allocation to ICDC is much more than as compared to what they did during all their tenures put together.

About the Urban Renewal Mission, it is the UPA Government which has started this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, you have already taken more than 25 minutes. Please conclude now.

SHRI K.S. RAO : Sir, give me just five minutes. I would conclude within five minutes.

Similarly, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was conceived only by this Government. To come to the rescue of the urban poor, Rs. 4,995 crore have been allocated now. They are ready to allocate something more, right up to Rs. 6,254 crore. Apart from this, they are taking into account the areas and regions of the States which are backward. In this regard, a separate allocation has been made with a grant of Rs. 5,000 crore.

In this manner, the Budget reveals that this time, the poor man is taken into consideration, and it is realised that unless the allocations are made, unless the income of the poor in the rural areas increased and unless their purchasing power goes up, there is no solution for this country. No matter whatever be the growth in industry; no matter how much wealth is generated in this country, unless their purchasing power is increased, it will not help. Some industrialists may manufacture 10 lakh motorcycles. But who will purchase it? About 65 per cent of our population is living in the villages. It is they, who should purchase them. But these manufactures would send them to Africa other countries leaving their own people. If the people below poverty line in

this country are not taken care of by these industrialists, there would be no solution. These industrialists are today earning crores of rupees for the sake of other countries.

Therefore, people living below poverty line in the rural are to be taken care of, and this is what this Government has done in this Budget. That is what this Government is taking up.

Sir, though I belong to Congress party, I have something to mention to our hon. Finance Minister. I appreciate the allocations made by him. But he has forgotten the basic point. What is wealth? Wealth has come out of the sweat, out of the skills of the human being. But I am sorry that enough allocation has not been made for the development of the human skills in this Budget. If Japan has come up, if South Korea has come up, if Malaysia has come up or if Singapore has come up, it is because of the skills that they have got. So, the skills of all the poor people below poverty line have to be increased. Today, a unskilled person is earning Rs. 50 per day. But by increasing the skills, everyone of us would happily give him Rs. 100.

In any place, be it a town or a village, if you want a good driver, you are not getting him; if you want a mechanic to repair your car or scooter, you are not getting him; if you want a good carpenter or plumber, you are not getting him. If you get a good skilled man, you would even be prepared to pay him Rs. 200. But if a person is not a skilled one, you would not pay him even Rs. 50. So, the skills of the citizens in this county has to be increased. All efforts must be made. Rupees 4 lakh crore worth wealth can be generated in this country just by improving the skills of the people living below poverty line. I am not talking about the entire population of this country.

The hon. Minister must please think of them. Now, the hon. Minister would say that he is not the Minister concerned; let some other Minister decide it. But however the Minister concerned, must do it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Rao, please conclucd now.

SHRI K.S. RAO : Sir, just give me two-three minutes. I have got only four to five points.

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

SHRI K.S. RAO : I am just concluding.

Sir, about water resources, I do support the inter-linking of the rivers. What the farmers require is not any donation or charity from the Government or anybody. What they want is timely water for irrigation. Our farmers are prepared to generate more than our imagination. We should think of them. If he were to increase the GDP by one per cent, he is struggling like anything. This struggle would not be required if our farmers are given timely water. They would generate enough wealth and make our GDP as 12 per cent, not only 10 per cent.

Similarly, FCI is proving as a white elephant. Rupees 20,000 crore worth is the food subsidy. I am not against giving subsidy to the poor. But the subsidy is not reaching the poor. It is going to the Food Corporation of India. A large number of self-help groups, particularly, with women members are coming into existence. Their performance is excellent[KD37]. If the responsibility is given to them by giving loan at a lower rate of interest, say three per cent, they will not only purchase and transport paddy but also convert it into rice, stock it in their traditional way and then supply it to all the Fair Price Shops in the country throughout the year. At present, the FCI procures paddy from the farmers, transports it to the rice mills which convert it into rice by taking conversion charges and then send it to either Punjab or Madhya Pradesh where it is being stocked in the godowns. They do not take care of it and as a result 25 per cent of it gets rotten. They either keep it in the open or it gets wetted so much that it is not in a condition to be consumed by even animals, leave alone human beings. We have reached at this pathetic stage. I have seen a number of times that thousands and thousands of tonnes of foodgrains, which are not fit for consumption, are auctioned but they do not fetch any money. Why should we waste our money?

The other day I was talking to the hon. Minister of Agriculture and he said that what I was saying was right. He said that the Government has made an Act to give food security to all the countrymen. When did the Government pass that Act? It was passed at a time when the food production in the country was less and we had to import foodgrains from outside. But we have passed that stage and now we have so much of production that we are exporting foodgrains to other countries. So, I request the hon. Minister to take it up in the Cabinet Ministers' meeting and see that FCI is wound up and the consequent savings can be utilised for providing health insurance to all the people below poverty line.

Every poor man in the country cannot get treatment in the Government hospitals. He cannot afford to pay the bills of corporate sector or private nursing homes. Although we have lakhs of doctors but no MBBS doctor will prefer to go to the village and set up a nursing home for the poor people. So, if the Government provides health insurance to all the people below poverty line then even those doctors who are reluctant to go to the villages will go and set up their nursing homes in the villages. The Government does not need to provide so much of money in the Budget for the health sector and the same money can be utilised for providing health insurance to all poor people or the marginal poor so that they are not at the mercy of any doctor, politician or official to get nice treatment.

So, some of these schemes, like, skill development, inter-linking of rivers, health care insurance for all the poor, winding of FCI and above all crop insurance are very important. If some godown, worth crores of rupees, of an industrialist is to be gutted, we are prepared to pay compensation to him. What crime a poor farmer has committed? He is made to suffer for no fault of his. He works hard in the fields for six months and when his crop is ready and he is expected to get two tonnes of paddy for every hectare of land, suddenly a cyclone or a flood comes in and his entire crop is washed away. Though it is not his mistake, yet he will not be provided any crop insurance. The Congress Government during Shri Rajiv Gandhi regime, thought of giving crop insurance scheme to the farmers but that scheme was not fully serving the needs of the people. I request the hon. Minister to take up the Crop Insurance Scheme and apply it to all the individual farmers. The Government should provide relief – if not immediately now at least in this year - on the basis of not *mandals* but village, to all the farmers who are working throughout the year.

I have a few such things to suggest. I will write to the hon. Minister on all these matters. I would also request the hon. Minister to cut down red tapism, which is eating into the lives and economy of this country. With these few words, I thank the hon. Minister for giving a good Budget to the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Members, who want to lay their written speeches on the Table of the House, can do so. Those will be treated as part of the proceedings.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): My friend, Shri K.S. Rao has mentioned the name of the then Chief Minister of Andhra Pradesh..... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए, तब आप यह बात कहना।

...(व्यवधान)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, that is on record. Please allow me to speak. I am not criticising anybody.

उपाध्यक्ष महोदय :मैंने उसी समय उनका नाम निकलवा दिया था।

...(व्यवधान)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, he has mentioned about the TDP workers. Since both the Andhra Pradesh Government and the Central Government are under the regime of Congress, I request the Government to appoint a CBI inquiry to find out the culprit.... (*Interruptions*[R38])

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Budget but this does not mean that we are very happy. We support it with some degree of disappointment also. They have tried to adhere to the pronouncements made in the National Common Minimum Programme. There is a marked departure from what the previous Government had been doing. They have appropriately been cautioned that

reckless and desperate disinvestment route can never contribute to the growth of this country. But we have been ruining the country by going through that desperate route only.

What is to be noted are the allocations given to the eight flag ship schemes. I would not say that they are too inadequate because then the Finance Minister would say that it could never be adequate. It is always relative. It is low in terms of the expectations of many partners including the Congressmen, our countrymen and even, of course, the Left. The Government should have addressed more on the burning issue of unemployment.

In the last Budget, the hon. Finance Minister had tried to concretise how during the Tenth Plan period and spilling over to the Eleventh Plan period, five crore jobs would be created. He had mentioned in the food processing sector – 2.5 crore jobs, textile sector 1.2 crore, etc. would be created. In such a way, he had given a picture about five crore jobs. I would like to know from the hon. Finance Minster during 12 months how many such jobs have been created. If you look at the rural areas -- I am not quoting any unofficial statistics – in the Economic Survey, the results of the 60th round of NSSO's survey on employment and unemployment situation conducted during January to June 2004 are now available.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is related to the entire period.

SHRI RUPCHAND PAL : Yes. The 60th round estimates of unemployment rate based on the current daily status, in 2004 – NDA and India Shining times – the males at 9.1 per cent up to 5.6 per cent in 1993-94 in rural areas and at 8.1 per cent up to 6.5 per cent in the urban areas… (*Interruptions*) I fully agree with you but do not support them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Yerrannaidu, no running commentary, please.

SHRI RUPCHAND PAL : This period was in NDA Government's regime. But this is not a factor to be taken into consideration that it was their time. But during this period also, how much jobs could be created. If you look at the figures, in 2001, we find that

in the 10 year period since the reforms process, the job opportunities had sharply come down both in the rural areas and the urban areas. There is a misconception created by some interested people as if the Left is against the economic reforms. But today what they are advocating as economic reforms is being equated with unemployment, more suffering and more poverty[r39]. That is the situation.

I was reading a report that the number of billionaires in India are growing at double the rate as compared to other countries in the world, that is, at 14 per cent. If I am not mistaken, there are more than 78,000 billionaires in the country today. Again, the same report puts the number of people living below poverty line at an estimated 26 crores. This estimation of people living below poverty line is wrong because they are based on limited parameters. I believe, the definition of poverty needs to re-assessed. I would not like to go into that debate right now.

Sir, there is an agrarian crisis in the country today. In the Tenth Plan the growth in this sector was targeted at four per cent. But the growth in this sector so far has been hovering around 1.7 per cent to 1.8 per cent and I believe even by the end of the Tenth Plan period we would not be able to achieve the targeted growth of four per cent in this sector. We are an agriculture based economy where 67 to 68 per cent of our population live in the countryside and are engaged mostly in agriculture. Not only it is the situation in regard to agriculture, even in respect of availability of foodgrain we seem to be in a period of the Great Famine. The hon. Minister may like to argue saying that now people are not merely dependent on cereals but they are taking something else as well. The point is that our agrarian sector is in serious crisis. The Government, of course, is quite conscious about that. I know they are conscious about it.

The Government had set up one National Commission under the Chairmanship of Dr. Swaminathan, a very capable and reputed person to head such a Commission. But I am very unhappy about the fact that hardly any major recommendation of that Commission has found a place in the Budget presented by the hon. Finance Minister this year. I do not mean to say that the Government has not considered the recommendations at all, but whatever has been considered is just not enough, rather it is very less. If the hon. Minister would allow me to use the word, I would say, `it is inadequate'.

Loans to farmers to be made available at seven per cent interest rate of course is a relief in the given situation when peasants and farmers are committing suicide in such large numbers all across the country. But this relief is just a peanut to them. Twenty-two per cent of the agricultural population in the country is still today dependent on loans from the private moneylenders and only 27 per cent have access to institutional finance and half of the population engaged in agriculture do not even have access to agricultural credit. I am happy about the fact that the concerns of the tenant cultivators have been addressed by the hon. Finance Minister and the banks have been asked to take care of their concerns. But the Government has not considered Dr. Swaminathan Commission's two vital recommendations about a Price Stablisation Fund and about crop insurance for all. That is very unfortunate. But still we are supporting this Government for some different reasons. It is because the previous NDA Government was even worse than this. At least this Government is trying and are willing to listen to us. They have said that they are passionate about these issues. Even such kind of words and assurances were not heard of in the NDA regime.

Sir, there are burning issues like employment and agrarian crisis. The hon. Minister has stated that this Government believes in growth and not jobless growth. But if it has to be a job-friendly growth, then the Government needs to re-orient their economic outlook, certainly not in the way of the Washington Consensus[snb40].

We are [bru41]not against economic reforms if they are good for the country, if they are good for the countrymen, if they are good for agriculture and industry. In a country where 40 per cent of the employment can be provided by the small scale industries, by the cottage industries, by the traditional industries, hardly any attention has been paid. The Minister will say that the new Bill is coming up. But there we find that there is more emphasis on labour reforms and contract labour. There is no social security. They are promising that they shall bring a Bill to ensure jobs for 92 per cent of the work force in the unorganised sector. But still it has not come. The budget hardly reflects such a need.

Unemployment is rampant. The Government is trying to follow the down-sizing in the organised sector. There is a ban on recruitment and there is rampant outsourcing in the organised sector. The example of China is most cited. China is a

manufacturing country only in IT. You cannot address the problem of employment. For a country like India, if real agricultural reforms are brought, we are the best supports for them. We will support if it is good for the people. Land reforms is about giving land to the people who are landless, in order to encourage them. Then comes adequate and timely credit, marketing facility including prices of the commodities. There is hard labour. If a reform is brought in these areas, we are the first to support you. But all your reforms mean that the fruits of reforms will be appropriated by a handful of billionaires. The number of billionaires is rising. Poverty is rising. Farmers are committing suicide. Even the educated people are standing in the queue. They have become so frustrated that sometimes they even do not register their names in the employment exchanges. What will be the outcome? Frustration. And what will frustration lead to? It will lead to what we have found in the North-East and elsewhere. There are external forces also who are out to exploit the frustrated ones. So, employment requires proper planning. Planning is required for manufacturing and appropriate support to the agriculture. Small scale sector is having problems. There are many Committees about upgradation of their technology, timely availability of raw materials, timely availability of adequate credit and marketing facilities for marketing the products both qualitywise and pricewise.

The Minister and myself have seen the position in China. But one thing should be noted. India should not imitate China. Yes. There is a wrong concept. India should have a model. Gandhiji wanted to have one model and Panditji wanted to have a slightly different model. There have been differences and ultimately, we are evolving our own model and that model must be labour-intensive model, agriculture-oriented model, small scale-oriented model and not simply IT-oriented model. We have our areas of strength in pharmaceuticals. We have our areas of strength in engineering and food processing. The Minister knows better than I do. But I am disappointed to see that the problem of unemployment has not been addressed. The problem of crisis in agriculture has not been addressed. Rather it is a repetition of some cliches. I think the Minister has made certain cliches like this and this will be done like Bharat Nirman, etc. I do not say that nothing has been done. There is remarkable achievement and we have a share in it. For the first time in free India, there is a National Employment Guarantee Scheme[bru42].

We are proud of it and they also must be proud of it. It is a coalition Government based on the National Common Minimum Programme. There is an agreement on the National Rural Employment Guarantee Act. That is an achievement. But that should be vigorously pursued. An amount of Rs. 40,000 crore is required to implement it. As it exists today, we are providing for only 100 days of work, for only one able-bodied person and confined only to 100 districts. If we have to cover all the other districts, which includes some urban areas, give employment to more than one able-bodied person and extend it from 100 days to 180 days, then it would require more funds. Now, it is very meagre and low.

With regard to the existing industries, there is hardly any vision. The Government, of course, has not taken the disinvestment route, which is very easy. Selling the property, selling the family silver and meeting the revenue deficit, which the NDA Government was doing, is easy. There are potential public sector undertakings, which given the necessary and timely support, can turn around. Look at the steel sector. Steel sector was ailing for some time. People were telling that Durgapur Steel Plant and other steel plants were sick. See what happened now! I congratulate the hon. Finance Minister and also the Minister of Industries for having extended support to some of the public sector undertakings. But there are many others which also need support. But unfortunately, there is no reference for revival and rehabilitation of these public sector undertakings.

The hon. Prime Minister once said that he does not believe in privatisation as an ideology. A very eminent industrialist once asked, "Is there any private Sector in this country?" He went on to say that all the private sector companies are using only the Government money, bank money and public sector money. He made a mention of a very very important private company which was being managed with just three